

पहले मुख्य समाचार।

- प्रदेश में जल्द लागू की जायेगी एक जिला एक व्यंजन-ओडीओसी योजना। योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा-वैश्विक स्तर पर स्थापित होगी प्रदेश की पाक कला।
- मुख्यमंत्री ने की सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक जोन की कार्ययोजना की समीक्षा। कहा- हर जोन में स्थापित होंगे सरदार पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केन्द्र।
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चन्दौली से कई जिलों में बनने वाले न्यायालय परिसरों का करेंगे शिलान्यास।
- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए कल, 31 जनवरी और एक फरवरी को राज्य में चलाया जाएगा विशेष अभियान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं से की सक्रिय सहभागिता की अपील।

एक जिला एक व्यंजन-ओडीओसी योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एमएसएमई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण खान-पान परम्परा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिये ओडीओपी योजना की तर्ज पर जल्द ही ओडीओसी योजना का शुभारम्भ किया जायेगा। ओडीओसी योजना से उत्तर प्रदेश की पाक कला वैश्विक स्तर पर स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि मथुरा का पेड़ा, सिद्धार्थनगर की रामकटोरी, बाराबंकी की चन्द्रकला, हाथरस की रबड़ी और वाराणसी की लौंगलता जैसी मिठाइयां और व्यंजन केवल भोजन नहीं बल्कि स्थानीय विरासत, कौशल और आर्थिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें गुणवत्ता, पहचान और बाजार उपलब्ध करा कर प्रदेश की सांस्कृतिक ताकत को आर्थिक शक्ति में बदला जायेगा। मुख्यमंत्री ने ओडीओसी योजना को पारम्परिक कारीगरों, हलवाइयों और छोटे उद्यमियों के लिये महत्वपूर्ण बताते हुए हर जिले के विशिष्ट व्यंजनों की पहचान कर उन्हें विशेष क्लस्टर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक जोन की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को केवल निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता का केन्द्र बनाया जाय। समीक्षा बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में न्यूनतम पचास एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल में औद्योगिक और रोजगार जोन विकसित किया जायेगा। हर जोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने नई योजना को ओडीओपी और एमएसएमई से जोड़ने की आवश्यकता जतायी। एक रिपोर्ट-

सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक जोन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह परियोजना ओडीओपी, एमएसएमई और कौशल विकास योजनाओं के साथ समन्वय बनाकर लागू की जाय ताकि स्थानीय उत्पादों, उद्योगों और युवाओं को एक साझा मंच मिले। उन्होंने नियमित समीक्षा स्पष्ट टाइम लाइन और जमीनी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी और उत्तर प्रदेश को रोजगार आधारित विकास मॉडल के राष्ट्रीय उदाहरण के रूप में स्थापित करेगी। समाचार कक्ष से रीतेश।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आह्वान किया है कि वे किसी एक खेल का चयन कर उससे जुड़ी प्रतिभाओं को तराशें। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया।

उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को प्राथमिकता का विषय बनाया। अब तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग-अलग विभागों में उन्हें सीधे नौकरी दी है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंदौली से एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बनने वाले न्यायालय परिसरों का शिलान्यास करेंगे। इनमें चंदौली के साथ ही औरैया, महोबा, शामली, हापुड़, आगरा और बहराइच के न्यायालय परिसर शामिल हैं। कार्यक्रम को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी परिक्षेत्र पिपूष मोर्डिया ने कल कार्यक्रम स्थल पहुंच कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उधर, चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने बताया कि चंदौली में बनने वाले नए न्यायालय परिसर का काम लगभग अट्ठार महीनों में पूरा किया जाएगा।

जनपद चंदौली में भी एक परियोजना है इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जिसकी लागत करीब रुपये 236 करोड़ है। उसमें 37 कोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ में एडवोकेट्स के चेंबर भी उसमें बन रहे हैं। साथ ही साथ अपने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज जस्ट आपका रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। 18 महीने के यह प्रोजेक्ट्स हैं और करीब अप्रैल 2027 तक यह प्रोजेक्ट्स का कंलीशन टाइम लाइन है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल अयोध्या के महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय में भगवान श्री राम की 35 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित गोष्ठी को भी संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज के युवा रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को डिजिटल माध्यम से जीवंत कर नई पीढ़ी को मर्यादा, कर्तव्य और सेवा का संदेश दे सकते हैं। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का स्वर्णिम दौर बताया, जहां तकनीक और भारतीय संस्कृति मिलकर विश्व को प्रेरणा दे रही हैं।

प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर के तहत कल इक्तीस जनवरी और एक फरवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि विशेष अभियान में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, अप्राप्त श्रेणी में चिन्हित मतदाता सूची और अनुपस्थित मतदाता या डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची बूथ पर उपलब्ध रहेगी। एक रिपोर्ट.....

विशेष अभियान के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इन तिथियों के अलावा जनपद स्तर पर अन्य तिथियों पर भी अभियान चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन पुनरीक्षण कार्यक्रम की गहन समीक्षा सुनिश्चित करें। श्री रिणवाने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि निर्धारित विशेष अभियान तिथियों पर अपने संबंधित बूथों पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें ताकि मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटिरहित बनाई जा सके। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

केन्द्र सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले, नकली और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में तीन दिवसीय इण्डिया फूड एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश का खाद्य प्रसंस्करण हब बनाना है। श्री मौर्य ने कहा कि इंडिया फूड एक्सपो जैसे आयोजन प्रदेश के किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं।

प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। हालांकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिलों में सुबह कोहरे के बाद पिछले दो दिन दोपहर में धूप निकली और लोगों को थोड़ी राहत मिली। आज सुबह से प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कम होने से सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ा है और कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।
